संख्या-3/2023/ 1114 /004-53-2002-002-2-2021-44बजट/2018

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 10 जनवरी, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष चतुर्थ किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-439/ दुग्ध-4/ नियो0/उ0प्र0रा0दु0परि0वि0सहा0(237)/2022-23, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि रू0 112.20 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-11/2022/ 227/001-53-2002-002-2-2021-44(बजट)/18, दिनांक 18 अप्रैल,2022 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 37.40लाख, शासनादेश संख्या-26/2022/ 610/002-53-2002-002-2-2021-44(बजट)/18, दिनांक 04 अगस्त, 2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 18.70 लाख एवं शासनादेश संख्या-30/2022/809/003-53-2002-002-2-2021-44(बजट)/18, दिनांक 20 अक्टूबर,2022 के द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 28.05 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त के सापेक्ष उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 112.20 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 28.05 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 26.88 लाख, (रूपये छब्बीस लाख अटठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
2. पूर्व में अवशेष धनराशि के उपभोगोपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।
4. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा तथा मानक मद से विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
5. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव, राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।
8. वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का उत्तरदायित्व होगा।
9. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

10. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
11. कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून,2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 26,88,000 (रुपये छब्बीस लाख अट्ठासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 016 लेखा शीर्षक 2404001021000 उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-354-X-2022-23, दिनांक: 2-1-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-3/2023/ 1114 /004-53-2002-002-2-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा),प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0,लखनऊ/प्रयागराज।
3. सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें ।
10. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।